

अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के वोटर्स ट्रम्प के समर्थन में

हालांकि हैरिस भारतीय मूल की हैं पर इण्डो अमेरिकन वोटर्स को वे पसंद नहीं हैं

—अंजन राय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 5 नवंबर। अमेरिका की जनता मतदान करने जा रही है, ऐसे में एक स्पष्ट निर्णय यह सामने आया है कि अमेरिका के लोग डॉनल्ड ट्रम्प तथा कमला हैरिस के बीच आधे-आधे बंटे हुए हैं।

राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान कुछ आश्चर्यजनक बातें भी हुई हैं—पारंपरिक जनाधार बदल रहे हैं और नई वफादारियाँ उभर रही हैं। उदाहरण के लिए, अश्वेत मतदाताओं को लें, वे पारंपरिक रूप से हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मतदान करते थे।

लेकिन, इस बार मतदान ट्रम्प व हैरिस के बीच विभाजित है। इस बार कोई अश्वेत मतदाता, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के लिए अपनी पारंपरिक पसंद के बजाय ट्रम्प के पक्ष में है।

दूसरी स्पष्ट बात यह है, बुद्धिजीवियों का समर्थन, हैरिस की तरफ इकट्ठा हो गया है और डॉनल्ड ट्रम्प का डटक विरोध कर रहा है। इन लोगों को हैरिस का समर्थन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने मुख्य रूप से ट्रम्प के प्रति नफरत के कारण ऐसा किया है। इस बार सभी बुद्धिजीवी हैरिस के झण्डे के पीछे एकजुट हो गए हैं।

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हासिल करना होगा। वर्तमान में 50 स्टेट्स हैं इसलिए जीतने के लिए 26 वोटों की जरूरत होगी। बाहरे संशोधन के इस प्रावधान का अमेरिका के इतिहास में सिर्फ एक बार सन् 1800 के चुनावों में इस्तेमाल हुआ था। यह एक दुर्लभ असाधारण घटना है। लेकिन समान मत मिलने की स्थिति से निपटने के लिए यह व्यवस्था की गई है। ए.आई. ने चुनाव नतीजे आने के दौरान असंतोष बढ़ने की संभावना बताई। और चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शन, मार्च, रैली जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ए.आई. ने तनाव बढ़ने, हिंसा होने की चेतावनी दी। हाल ही में आए ए.बी.सी. न्यूज/इप्सा सर्वे के अनुसार सिर्फ 29 प्रतिशत अमेरिकन मानते हैं कि ट्रम्प हार स्वीकार कर लेंगे, इससे अंशाका है कि चुनाव नतीजों के बाद हिंसा होगी। इसी के चलते ब्रांशिगटन डी.सी. में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। चुनाव देश को एकजुट करने की बजाय देश को बांट रहे हैं और अनिश्चितता बढ़ा रहे हैं। रॉयटर्स ने बताया कि जिन राज्यों में कड़ा मुकाबला है वहां के अधिकारी

अफवाहों, साजिशों की खबरों, धमकियों व हिंसा की आशंका वाली खबरों पर भरोसा कर रहे हैं। फिलाडेल्फिया डेट्टीयट और एटलांटा राज्य जिनके लिए ट्रम्प अक्सर फर्जी वोटिंग के दावे करते हैं, वहां अधिकारियों ने मतगणना प्रक्रिया की सुरक्षा के उपाय किए हैं। फिलाडेल्फिया में जहां मतगणना होनी है उस जगह की सुरक्षा के लिए कांटेदार बाड़ लगाई गई है। डेट्टीयट और एटलांटा में मतदान केन्द्रों के खिड़की, दरवाजों पर बुलेटप्रूफ कांच लगाए हैं। विस्कोन्सिन में चुनाव कर्मियों को डीएकेलेस टैकनीक्स का प्रशिक्षण दिया गया है तथा मतदान केन्द्रों में बच निगरानी का रास्ता बनाया। माहौल खराब होने की स्थिति को देखते हुए एरिजोना, जहां 2020 में चुनाव में फर्जीवाड़े के दावे किए गए थे, में प्रशासन ड्यूटी अफवाहों से निपटने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है, खासकर फर्जी वोटर्स की काल्पनिक तस्वीरों से। अन्य राज्यों को भी सुरक्षा को लेकर भारी चिंता है। रॉयटर्स ने बताया कि ब्रांशिगटन के गवर्नर ने नैशनल गार्ड यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है। यहाँ कमला हैरिस के भारी

अंतर से जीतने की उम्मीद है। यह गत दिनों बैलेट बॉक्स जलाने की खबर आई थी। सी.एन.एन. ने बताया कि नेवाडा और अरिजोना में नैशनल गार्ड यूनिट्स को तैयार रखा गया है। गार्जियन ने ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख किया जिसमें चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की गई थी, जिसमें अरिजोना व ब्रांशिगटन की बैलेट बॉक्स जलाने, पैनिस्लेनियामें बम की धमकी दिए जाने, सैन एंटीोनियों में चुनाव कर्मियों व वोटर के बीच हाथा पाई, और एरिजोना शेरय में हथियार बन्द आदमी की गिरफ्तारी घटनाएं प्रमुख हैं। उक्त व्यक्ति की साजिश बड़े पैमाने पर हिंसा करने की थी। इन्टरनेशनल क्र्राईसिस ग्रुप (आई.सी.जी.) ने चेतावनी दी है कि चुनाव सम्बन्धी हिंसा की संभावना बहुत ज्यादा है। बड़े पैमाने पर दलगत ध्वष्टीकरण होने से नतीजों को अस्तित्व से जोड़ कर देखा जा रहा है। राजनैतिक हिंसा के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है। अप्रैल में हुए एन.पी.आर./पी.बी.एस. पोल के अनुसार 20 प्रतिशत अमेरिकन मानते हैं कि देश को ठीक करने के लिए हिंसा जरूरी है।

सी.बी.आई. ने छापों में 50 लाख रुपए बरामद किये

रांची, 05 नवंबर। झारखंड में विधानसभा चुनाव से आठ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी और उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सी.बी.आई. ने पंकज मिश्रा के करीबीयों के 20 ठिकानों पर छापेमारी कर 50 लाख रुपये कैश जब्त किया है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित 3 राज्यों में 20 स्थानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपये नकद, एक किलो सोना और चांदी के कुछ आभूषण बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, साहिबगंज के

■ जिन पर छापे पड़े वे सभी हेमन्त सोरेन के करीबी, पंकज मिश्रा के नजदीकी सहयोगी हैं।

11 जगहों पर छापेमारी हुई तो रांची में 3 और कोलकाता और पटना में एक-एक जगह पर रेड किया गया। पंकज मिश्रा बरहट विधानसभा के विधायक हेमन्त सोरेन के प्रतिनिधि हैं। पंकज मिश्रा और कई लोगों के खिलाफ अवैध खनन मामले में सी.बी.आई. ने 2023 में एफ.आई.आर. दर्ज की थी।

धारीवाल पर फिर से चलेगा एकल पट्टे का मुकदमा

जयपुर, 5 नवंबर। प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनके तहत तत्कालीन यू.डी.एच. मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. और अदालती कार्रवाई को निरस्त करने के साथ ही, पूर्व आई.ए.एस. जी.एस. संघू सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को हरी झंडी दी गई थी। जस्टिस सुर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयाँ की खंडपीठ ने यह आदेश अशोक पाठक की स्पेशल लीव पीटीशन (एन.एल.पी.) पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने हाईकोर्ट को

■ सुप्रीम कोर्ट ने शांति धारीवाल व अधिकारियों को राहत देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर हाईकोर्ट को पुनः सुनवाई कर 6 माह में उचित आदेश पारित करने को कहा।

कहा है कि वह प्रकरण की पुनः सुनवाई कर छह माह में उचित आदेश पारित करें। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने बताया कि गत अप्रैल माह में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश शपथ पत्र में प्रकरण में कोई आपराधिक मामला नहीं बनने की बात कही थी, लेकिन इस दौरान उनसे

सलाह नहीं ली गई। वहीं, अब नया शपथ पत्र पेश कर हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द करने की गुहार की गई थी। अति. महाधिवक्ता शर्मा ने बताया कि मामले में ए.सी.बी. ने तीन क्लोजर रिपोर्ट अदालत में पेश की थीं, वे धारीवाल सहित अन्य अधिकारियों से प्रभावित थीं। इन रिपोर्टों में सभी तथ्यों को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में ए.सी.बी. कोर्ट ने दो क्लोजर रिपोर्टों को खारिज कर दिया था और तीसरी

पर कोई निर्णय नहीं हुआ था। इस दौरान मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने गत जनवरी माह में पूर्व आई.ए.एस. जी.एस. संघू, निष्काम दिवाकर और ऑंकार मल सैनी के खिलाफ मुकदमा वापस लेने को सही माना और धारीवाल के खिलाफ प्रकरण खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आर.टी.आई. कार्यकर्ता अशोक पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में एन.एच.पी. दायर की थी, जिसमें कहा था कि शिकायतकर्ता से राजीनामे के आधार पर केस को रद्द नहीं किया जा सकता। मामले के अनुसार, साल 2014 में रामशरण सिंह की ओर से गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी को एकल पट्टा जारी

संसद सत्र 25 नवम्बर को शुरू होगा

नयी दिल्ली, 05 नवंबर। सरकार ने संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित कराने की मंगलवार को घोषणा की। इस दौरान 26 नवंबर को संविधान दिवस पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया जायेगा।

शीतकालीन सत्र 20 दिसम्बर तक चलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी देते हुये कहा, भारत सरकार की सिफारिश पर माननीय राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदन के शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक आहूत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

संसद की कार्यसूची के अनुसार, शीतकालीन सत्र की अर्वाधि में संशोधन भी किया जा सकता है।

रिजिजू ने बताया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर संविधान को अंगीकार किये जाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक समारोह संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित किया जायेगा।

फिर से भाजपा के हिंदुत्व आइकन बने योगी आदित्यनाथ

योगी का “बटेंगे तो कटेंगे” नारा काफी चर्चित हो रहा है

— श्रीनन्द झा —

— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —

नई दिल्ली, 5 नवंबर। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा में भले ही कमी आ गई थी, लेकिन उन्होंने फिर से वापसी करते हुए, भाजपा में हिन्दुत्व के प्रतीक के रूप, अपना पूर्व कद फिर से हासिल कर लिया है।

झारखण्ड और महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों के प्रकार में योगी की जबरदस्त मांग हो रही है तथा उनका “बटेंगे तो कटेंगे” नारा भाजपा के हलकों में जबरदस्त हिट हो रहा है। मथुरा में 22 अक्टूबर को आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत के साथ हुई उनकी मीटिंग के दो दिन बाद, आर.एस.एस. के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले योगी की इस टिप्पणी को, उनके इस नारे को दोहराया था, जो योगी ने हरियाणा चुनावों में काम लिया था और काफी असरदार रहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी योगी के इस नारे का समर्थन किया बताते हैं।

रोचक बात यह है कि लोकसभा के चुनाव परिणामों के बाद, योगी 3 नवम्बर को प्रधानमंत्री से पहली बार मिले थे। इससे पूर्व, गत माह हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद, प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई

■ योगी ने हरियाणा की एक चुनावी सभा में यह नारा दिया था, समझा जाता है कि इससे भाजपा को भारी लाभ हुआ हरियाणा में और अब महाराष्ट्र व झारखंड में भी योगी व उनका यह नारा काफी लोकप्रिय हो रहा है।

■ संघ प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबाले और प्रधानमंत्री मोदी तक योगी के इस नारे के प्रशंसक हैं तथा उन्होंने इसका समर्थन किया है।

एन.डी.ए. के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में, वे प्रधानमंत्री के श्रोता के रूप में शामिल जरूर हुए थे। उस दिन, योगी ने गृहमंत्री अमित शाह तथा भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के साथ लम्बी मीटिंग भी की थी।

लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में हुई भाजपा की घोर पराजय के बाद के महीनों में, योगी कटघरे में खड़े करदिये गये थे तथा पार्टी के खोजी लोग यह कहने लगे थे कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा उन्हें पार्टी के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेगी। हाल ही में, आर.एस.एस. और भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ हुई मुख्यमंत्री योगी की मीटिंग ऐसे संकेत दे रही हैं कि उन्होंने, कम से कम फिलहाल तो, अपने अस्तित्व के संकेत पर विजय पा ली है।

योगी ने आज़ झारखंड में अपना प्रचार-अभियान कर दिया। उन्होंने एक

दिन में तीन जनसभाएं संबोधित कीं। हजारों बाग की सभा में उन्होंने अपना नारा दोहराया: “ये समय बंटने का नहीं है। कांग्रेस ने 1947 से देश को बांटा है।” योगी का “बटेंगे तो कटेंगे” नारे के महाराष्ट्र में भी गूंजने की संभावना है। महाराष्ट्र में योगी की सभाओं की तिथियाँ एवं स्थानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

23 नवम्बर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लायेंगी। इसके परिणामस्वरूप, राहुल और प्रियंका की टीमों में टकराव की स्थिति भी बन सकती है।

संगठन में बदलाव अपेक्षित भी है तथा जब भी यह बदलाव होगा, उस समय यह देखना बड़ा रुचिकर होगा कि कौनसा नेता किस खेमे से जुड़ा हुआ है।

‘यूपी मद्रसा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुए, इससे संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि मद्रसा एक मद्रसा शिक्षा के लिए वैध ढांचा उपलब्ध करा रहा है, जिसमें एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम के अलावा, धार्मिक शिक्षा का भी प्रावधान किया गया है।

अदालत ने कहा कि मद्रसों द्वारा उच्च शिक्षा की डिग्री देना कानूनी है क्योंकि यह यूनिवर्सिटी ग्रांन्ट्स कमीशन (यू.जी.सी.) एक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.पी. पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बैंच ने कहा कि जहां “मद्रसा एक्ट राज्य विधायिका की वैधानिक क्षमता के अन्दर है”, वहीं अधिनियम में “फाजिल” और “कामिल” के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री देना राज्य के दायरे में नहीं है यह यू. जी. सी. एक्ट की धारा 22 के प्रतिकूल है। यू.जी.सी. एक्ट उच्च शिक्षा के मानक एवं स्तर निर्धारित करता है तथा राज्य की विधायिका यू.जी.सी. एक्ट के प्रतिकूल उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने को कोशिश नहीं कर सकती।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “राज्य सरकार के अनुमोदन के साथ, बोर्ड ऐसे नियम बना सकता है, जो यह सुनिश्चित करें कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाएं, अपने अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना, अपेक्षित स्तर की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करेंगी।”

“जे.एम.एम....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डागा की जनसभाओं में कक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सत्तारूढ़ झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, जे.एम.एम. का वास्तव में अर्थ “जमकर मलाई मारो” है, अन्यथा जे.एम.एम. के नेताओं और उनके पी.ए. ने करोड़ों रुपए कैसे जमा किए होंगे।

उन्होंने कहा, नया राज्य बनने के बाद से अब तक झारखण्ड में 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उनमें से कई जेल गए, जबकि, भाजपा का एक भी मुख्यमंत्री जेल नहीं गया। उन्होंने कहा, जे.एम.एम. की ड्यूटी नाव पर कोई नहीं चढ़ना चाहता, और इसीलिए नई सरकार भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. की होगी।

राजनाथ सिंह ने पिछड़े आदिवासियों के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री जनमन योजना की बात की। उन्होंने कहा, साठ हजार आदिवासी गांवों को विकसित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा, इस बात की जांच होनी चाहिए कि आदिवासी, जो राज्य में सबसे ज्यादा थे, उनकी आबादी घटकर 28 प्रतिशत ही कैसे रह गई है।

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने लंदन के बैंक में 102 टन सोना “गिरवी” रखा था, जिसे मोदी सरकार धनतेरस के बाद वापस ले आई है।

रक्षा मंत्री ने यह घोषणा भी की कि गोपी दीदी योजना से हर महिला को हर महीने ग्यारह तारीख को 2100 रूपए मिलेंगे। इसके अलावा महिलाओं को 500 रूपए में रसोई गैस सिलिण्डर तथा 2 सिलिण्डर मुक्त मिलेंगे।

एजुकेशन प्री-समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग लेंगे



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों के मद्देनजर, कृष्ण कुणाल,

राजपुर, 5 नवंबर। राजजिंग राजस्थान से पूर्व, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमता विभाग तथा खेल एवं युवा मामलात के संयुक्त तत्वाधान में 6 नवंबर को “एजुकेशन प्री-समिट 2024” का आयोजन होगा। होटल इंटरकॉन्टिनेंटल, टॉक रोड, जयपुर में होने वाले इस शिक्षा सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे तथा उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, युवा मामलात एवं खेल, कौशल, योजना एवं उद्यमता विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शिरकत करेंगे।

समिट का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल तकनीकों का उपयोग और निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा करना है। प्री-समिट की